RAJHIN/2013/57037 Postal Regd. No. : Sriganganagar/252/2020-2022 Posted at Sriganganagar E-mail : sehkargaurav@gmail.com

सहकार गौरव

बैंक, सहकारिता, कृषि, डेयरी, पशुपालन, ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

वर्ष : 9 | अंक : 14 | पाक्षिक | पृष्ठ : 4 | 16 मई से 31 मई 2022 | श्रीगंगानगर (राजस्थान) | वार्षिक मूल्य : रुपए 250 | मोबाइल : 097820-56056

सीएम ने फसली ऋण जमा करवाने की अवधि बढ़ायी, डिफाल्टर होने से बचे राज्य के 4.50 लाख किसान

जयपुर, 8 मई। राजस्थान सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंकों से लिए गए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण जमा करवाने की अन्तिम तिथि 30 जून 2022 कर दी है। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से खरीफ ऋण जमा कराने की आखिरी तारीख बढाए जाने की सूचना दी। किसानों को अब ऋण चुकाने के लिए सात सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

यहां उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों के कारण, किसानों के हित को देखते हुए राज्य सरकार गत दो वर्ष से लगातार, किसानों को तीन माह का अतिरिक्त समय दे रही थी। वर्ष 2020 एवं 2021 में खरीफ ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढाकर 30 जून किया गया था। सामान्यतः फसली सीजन के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। पिछले दो साल में कोरोना वायरस संकट के कारण, ऋण जमा करवाने की तिथि 30 जून की गयी थी। यदि अंतिम तिथि तक ऋण जमा नहीं होता है, तो ऋण अवधिपार होने पर किसान को 9 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता है, साथ ही उसे पुनः फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिलता।

1550 करोड़ रुपए का ऋण अवधिपार, 4.50 लाख किसान डिफाल्टर

इससे पूर्व, ऋण जमा करवाने की तिथि नहीं बढाए जाने से प्रदेश के 4 लाख 50 हजार से अधिक किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ गये थे और केंद्रीय सहकारी बैंकों का 1550 करोड़ रुपए का फसली ऋण अवधिपार हो गया था। राज्य के दो बड़े जिलों - बाड़मेर में 550 करोड़ और जोधपुर में 400 करोड़ रुपए का फसली ऋण अवधिपार की श्रेणी में आ गया था। इन बैंकों की ओर से अपेक्स बैंक को ऋण वसूली की अवधि बढाए जाने की अनुशंसा भी गयी थी।

एकमुश्त समझौता योजना की अवधि भी बढ़ायी

दूसरी ओर सरकार ने ऋणी कृषकों को एक और बड़ी राहत देते हुए, कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2020 की प्रवर्तन अवधि एक बार पुनः बढ़ा दी है। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव नारायण सिंह की ओर से 11 मई 2022 को आदेश जारी कर बताया गया कि सहकारिता रजिस्ट्रार की अनुशंसा पर, कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2020 की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है।

सहकारिता विभाग के अनुसार, इससे पहले, कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना की प्रवर्तन अवधि 31 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी। योजना के अंतर्गत ऐसे ऋण प्रकरणों को शामिल किया जाएगा, जो ऋण 31 मार्च 2018 को अवधिपार हो चुके हैं और उसके पश्चात नियमित नहीं हुए हैं, अर्थात एनपीए हो चुके हैं।

नये सहकारी नगीनों को तराशने का कार्य आरम्भ

उत्तरदायित्व एवं सत्यनिष्ठा के साथ जनता के सेवक के रूप में कार्य करें - आंजना

जयपुर (सहकार गौरव)। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसम) में सहकारिता विभाग के नये नगीनों को तराशने का कार्य 12 मई से आरम्भ हो गया। संस्था एक्ट के तहत एनजीओ के रूप में पंजीकृत राइसम में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से नवचयनित 80 सहकारी निरीक्षकों के नये फाउण्डेशन कोर्स के शुभारम्भ अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना विशेष रूप से उपस्थित हुए।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता निरीक्षक बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तरदायित्व एवं सत्यनिष्ठा के साथ सहकारिता विभाग के माध्यम से जनता के सेवक के रूप में कार्य करें। उन्होंने कहा कि सहकारिता निरीक्षक एक आधार स्तम्भ के रूप में सहकारिता को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे में लोगों को अच्छी सेवा दें एवं नवाचार पर कार्य कर सहकारिता को आगे लेकर जाएं।

श्री आंजना ने कहा कि विभाग को 173 सहकारिता निरीक्षकों के पहले चरण में 80 निरीक्षकों का 5 जुलाई तक फाउण्डेशन कोर्स होगा तथा शेष निरीक्षकों का 7 जुलाई से फाउण्डेशन कोर्स प्रारम्भ किया जाएगा।

जनता की सेवा के रूप में कार्य करते हुए थ्री-डी का ध्यान रखें : वेंकटेश्वरन

एचसीएम,रीपा के महानिदेशक डॉ. आर वेकटेश्वरन ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से चर्चा करें, जो सिखाया जा रहा है उसे ग्रहण करें एवं पूछने में संकोच न करें। जनता की सेवा के रूप में कार्य करते हुए थ्री-डी यानी ड्यूटी, डिग्निटी एवं डिसिप्लेन का ध्यान रखें।

सहकारिता सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम : मुक्तानंद

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि सहकारिता सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम है। सहकारिता के समक्ष अनेक चुनौती हैं, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को सहकारिता के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण कर लोगों को राहत दी गई। उन्होंने कहा कि सभी निरीक्षक प्रशिक्षण के दौरान गम्भीरता से सीखें, आपस में सहयोग करें और अपना कौशल विकास कर दक्षता में सुधार लाए। राइसम निदेशक श्रीमती शिल्पी पांडे ने स्वागत उदबोधन के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। अतिरिक्त निदेशक राइसेम मुरारसिंह जाड़ावत ने धन्यवाद ज्ञापित कया। सहकारिता मंत्री के विशिष्ट सहायक आशीष शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार श्रीमती सुरभि शर्मा सहित विभागीय एवं राइसम अधिकारी, कर्मचारी एवं नवचयनित सहकारिता निरीक्षक उपस्थित थे।

जून-जुलाई में ही होंगे सहकारिता चुनाव

उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन के पंजीकरण एवं वार्डों के गठन की प्रक्रिया इसी सप्ताह आरम्भ होगी

श्रीगंगानगर (सहकार गौरव)। सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समिति में चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देना आरम्भ कर दिया गया है।

चुनाव के सम्बंध में राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से आयोजित वीसी के उपरांत अतिरिक्त रजिस्ट्रार-प्रथम, राजीव लोचन शर्मा की ओर से, समस्त इकाई अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 11 के अंतर्गत पैक्स, लैम्पस के उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन जारी करने की अवधि क्रमशः 17 मई एवं 21 मई को समाप्त हो रही है। वीसी में रजिस्ट्रार की ओर से दिये गये निर्देशानुसार, प्रावधान के अनुरूप 90 दिन की अवधि समाप्त होने के आगामी तीन दिन में उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत किया जाए, तदोपरांत 10 दिवस में वार्डों के गठन एवं वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न की जाए।

इससे पूर्व, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जून-जुलाई माह में प्रस्तावित चुनावों को लेकर 11 मई को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपनियमों को पंजीकृत करने एवं वार्डों के गठन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गये। चुनाव के दृष्टिगत इस महत्वपूर्ण वीसी में सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार-प्रथम राजीव लोचन शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार नियम कुमार विवेकानंद यादव, राज्य के सातों सम्भाग के खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं इकाई अधिकारी सम्मिलित हुए।

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी संजय माथुर की ओर से निर्देशित किया गया कि, चूंकि उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन को जारी करने के 90 दिन के उपरांत पंजीकृत किये जाने का प्रावधान है, इसलिए जिन समितियों द्वारा उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकार कर लिया गया है, अथवा इस बाबत ▸▸ शेष @ 4 पर

सोसाइटी ही ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों की नियोक्ता रहेगी!

जयपुर (सहकार गौरव)। राज्य सरकार और सहकारिता विभाग की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों के नियोक्ता निर्धारण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सरकार के पास सहकारी समिति कर्मचारियों के नियोक्ता निर्धारण अथवा कैडर ऑथोरिटी के गठन का अब कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दशकों से ग्राम सेवा सहकारी समिति ही अपने कर्मचारियों की नियोक्ता रही है, इसलिए इस व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का प्रश्न हीं नहीं उठता। वित्त विभाग भी ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों को राज्य सरकार या सम्बंधित केंद्रीय सहकारी बैंक का कर्मचारी बनाने के विषय पर अपनी मौखिक असहमति जता चुका है। सूत्र बताते हैं कि उच्च स्तर पर यह क्लीयर मैसेज जारी हो चुका है कि राज्य में पैक्स, लैम्पस कर्मचारियों के लिए न तो कैडर ऑथोरिटी का गठन होगा, न ही इन्हें बैंक अथवा राज्य सरकार का कर्मचारी बनाया जाएगा।

कैडर ऑथोरिटी पर वित्त व सहकारिता विभाग में हुआ मंथन : इससे पूर्व, नोहर विधायक अमित चाचाण की ओर से सहकारी समिति कर्मचारियों की मांगों के सम्बंध में सहकारिता मंत्री को प्रस्तुत पत्र के उत्तर में रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से बताया गया था कि कैडर ऑथोरिटी की पत्रावली वित्त विभाग और सहकारिता विभाग के मध्य परीक्षणाधीन है। दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य मैराथन मंथन के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स, लैम्पस) ही सोसाइटी कर्मचारियों का नियोक्ता रहेगी।

सहकारिता चुनाव में सहयोग नहीं करना हाईकोर्ट की अवमानना माना जाएगा - गर्ग

श्रीगंगानगर। राज्य में जून-जुलाई में प्रस्तावित सहकारी चुनाव को लेकर गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं इकाई अधिकारी संजय गर्ग द्वारा सोमवार को शाखा प्रबंधकों एवं ऋण पर्यवेक्षकों की वीसी का आयोजन किया गया। वीसी के दौरान, ब्रांच मैनेजर और लोन सुपरवाइजर्स को प्रस्तावित चुनावों को लेकर, सम्बंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से अद्यतन मतदाता सूची तैयार कर, उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया। एमडी श्री गर्ग ने वीसी में समस्त शाखा प्रबंधकों, ऋण पर्यवेक्षकों और ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापकों से चुनाव में सहयोग की अपेक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में करवाए जा रहे हैं। यदि इस कार्य में कोई समिति कर्मचारी अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगा या सहयोग नहीं करेगा, तो इसे उच्च न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। बैंक अथवा सहकारिता विभाग की ओर से ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

किसानों को अब 15 घंटे बिजली मिलेगी : भाटी

जयपुर (सहकार गौरव)। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को वीसी के माध्यम से

आयोजित बैठक में राजस्थान में बिजली की मांग, उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल की सिंचाई हेतु ब्लॉक आपूर्ति के समय में एक घंटे की बढोतरी की जाए। वर्तमान में किसानों को 4 घंटे के तीन ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसे बढ़ाकर पांच घंटे किया जाए। श्री भाटी ने बताया कि किसानों को अब रात्रि में 2 बजे से प्रातः 7 बजे तक, प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं अपरान्ह 12 बजे से सायं 5 बजे तक तीन ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जाएगी।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी को निर्देश दिए कि प्रदेश की उत्पादन इकाईयों से प्रतिदिन 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाए।

वर्तमान में उत्पादन निगम की इकाइयों से लगभग 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है।

कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर का अधिकाधिक प्रचार हो

मंत्री ने तीनों डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशकों को निर्देश दिए कि कन्ज्यूमर कॉल सेन्टर पर दर्ज होने वाली शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। किसानों द्वारा बिजली की समस्या को कॉल सेन्टर पर दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके साथ ही टोल फ्री नम्बर को जीएसएस, उपखण्ड कार्यालय एवं एफआरटी व्हीकल पर भी प्रदर्शित किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली शिकायतें दर्ज कराने में किसी प्रकार की समस्या नही हो।

कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से दिये जाए

श्री भाटी ने कहा कि किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। प्रचंड गर्मी को देखते हुए पीएचइडी के लम्बित बिजली कनेक्शन भी तुरन्त प्राथमिकता से जारी किए जाएं। उन्होंने किसानों को आगामी समय में दिए जाने वाले नए कृषि कनेक्शन एवं दिन के समय दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति को देखते हुए सिस्टम पर बढने वाले लोड के मध्यनजर 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी जीएसएस के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रसारण निगम को निर्देश दिए गए।

सहकार मसाला मेला के माध्यम से सहकारिता ने राजधानी में दर्ज करायी दमदार उपस्थिति

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला में 1.40 करोड़ रुपए की रेकार्ड बिक्री

जयपुर। सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (कॉनफैड) की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 में जयपुरवासियों ने जमकर खरीदारी की। सोमवार को समाप्त हुए इस दस दिवसीय मसाला मेला-2022 में 1.40 करोड़ रुपए की रेकार्ड बिक्री हुई।

समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और कॉनफैड के प्रशासक मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि यह मेला सहकारी समितियों के व्यवसाय में वृद्धि करने के अच्छे प्रयास का एक बेहतर प्लेटफार्म प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मसाला मेला के माध्यम से सहकारिता ने जयपुर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करायी है। सहकारिता की विश्वसनीयता और मसालों की गुणवत्ता के चलते लोगों को सहकार मसाला मेला का बेसब्री से इंतजार रहता है। हजारों लोगों ने सालभर के मसालों की एकसाथ खरीद की। केवल मसालों के दम पर एक बड़े आयोजन का सफल होना यह दर्शाता है कि यदि आपके उत्पाद में गुणवत्ता है और आप पूरी ईमानदारी व मेहनत से प्रयास करें, तो आपको अपने लक्ष्य को अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि इस साल दीपावली पर भी भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटाखों, गिफ्ट आइटम, ड्राईफ्रूट व मिठाई के साथ-साथ अन्य उत्पादों की भी बिक्री की जाएगी। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा, कॉनफैड के एमडी वी.के. वर्मा और उनकी पूरी टीम को तहेदिल से बधाई दी।

रजिस्ट्रार ने कहा कि आमजन को कॉनफैड के माध्यम से पहली बार 15 जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि सहकार मसाला मेले का वास्तविक लाभ किसानों और आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सहकारी संस्थाओं के विशेष उत्पाद सहकारिता के भण्डारों पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। रजिस्ट्रार ने कहा कि हम सहकारी संस्थाओं को आमजन की आवश्यकता के अनुसार तैयार करेंगे और उन्हें वन स्टॉप के रूप में विकसित कर एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवा उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेंगे।

इससे पूर्व, कॉनफैड के प्रबंध निदेशक वी.के. वर्मा ने स्वागत भाषण में रजिस्ट्रार, विभागीय अधिकारियों, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मेले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला में केरल, तमिलनाडु और पंजाब के अलावा 5 राज्य स्तरीय संस्थान, 15 जिला सहकारी होलसेल भंडार, 8 क्रय विक्रय सहकारी समिति, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा 27 अन्य प्राइमरी सोसाइटी, कुल 68 संस्थाओं ने भाग लिया। मेले में 10 प्रकार के साबुत गरम मसाले, 13 परम्परागत मसाले, 27 प्रकार के इंस्टेंट मसाले, 5 प्रकार के परम्परागत साबुत मसाले, 16 प्रकार के अचार, 26 प्रकार के शर्बत, 5 प्रकार की ठण्डाई, 5 प्रकार के मुरब्बे, 7 प्रकार की सूखी सब्जियां, ड्राईफ्रूट, डेयरी उत्पाद, खाद्यान्न एवं अनाज, तेल एवं अन्य खाने की सामग्री सहित 164 प्रकार के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए।

उन्होंने बताया कि इस बार अधिक तापमान को देखते हुए रजिस्ट्रार के निर्देश पर एयरकूल्ड डॉम की व्यवस्था की गयी, हालांकि इससे आयोजन की लागत में बढोतरी हुई, परन्तु इसका लाभ यह रहा कि लोगों ने दिन में भी खरीदारी की। लगभग एक लाख लोग मेला देखने और खरीदारी के लिए पहुंचे और एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक मसालों व अन्य उत्पादों की बिक्री हुई। उन्होंने बताया कि विभिन्न सहकारी संस्थाओं की ओर से मेले के आयोजन के लिए 71 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिला, जो अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने मेला स्थल उपलब्ध कराने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग का तथा बेहतरीन आवासीय व्यवस्था के लिए राइसेम, आईसीएम का आभार व्यक्त किया। साथ ही, इस सफलतम आयोजन में पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम देने वाले सहकारी अफसरों और कॉनफैड के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

इन सहकारी संस्थाओं को किया पुरस्कृत

समापन समारोह में श्रेष्ठ स्टॉलों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल, सीनियर ▸▸ शेष @ 4 पर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला – 2022 ने स्थापित किये सफलता के नये आयाम

जयपुर। सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (कॉनफैड) की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 ने राज्य की राजधानी में दमदार उपस्थिति दर्ज करायी। सहकारिता रजिस्ट्रार और कॉनफैड के प्रशासक मुक्तानंद अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन और दो चिरयुवा सहकारी अधिकारियों, मेला कमेटी के अध्यक्ष सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार विजय कुमार शर्मा एवं उपभोक्ता संघ के प्रबंध निदेशक वी.के. वर्मा ने मेला के तमाम इंतजामात को इतनी बारीकी और पेशेवराना अंदाज से अंजाम दिया, जैसे कोई एक से बढ़कर एक सुंदर मोती चुनकर अपने प्रिय के लिए खूबसूरती माला को पिरोता है। मेले के संयोजन के लिए गठित सहकारिता विभाग और कॉनफैड के अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम ने मेले के वातानुकूलित पंडाल (डोम), भव्य स्टेज, स्टॉल्स, कंट्रोल रूम, एयरकंडीशंड वीआईपी रूम, पेजयल व्यवस्था आदि एक-एक व्यवस्था का पूर्ण कुशलता के साथ प्रबंध किया। रात्रि को दूधिया रोशनी में नहाया सहकार मसाला मेला के विशाल व्हाइट डोम में किसी बड़े विवाह कार्यक्रम की झलक देखने का मिलती।

सहकार मसाला मेला में स्टॉल्स लगाने वालों को आईसीएम, राइसम और किसान भवन के वातानुकूलित कमरों में निःशुल्क ठहराने की व्यवस्था की गयी और उन्हें विश्राम स्थल से मेला ग्राउंड तक लाने व ले जाने के लिए एसी वाहनों की व्यवस्था की गयी। ऐसा प्रतीत होता था मानों हर रोज बारातियों का स्वागत-सत्कार किया जा रहा हो। मेले के आयोजन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी ने समर्पित भाव और पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जिसके दम पर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 अब तक का सबसे सफल आयोजन साबित हुआ।

ज्वाइंट रजिस्ट्रार श्रीमती सोनल माथुर और मुरार सिंह जाड़ावत ने अन्य साथी अधिकारियों के साथ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और स्वयं भी भागीदार बने। जोनवाइज कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौरान आमतौर पर, जिस सम्भाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, उसी संध्या के दौरान, सम्बंधित जोन के सहकारी अधिकारियों ने अनिवार्य रूप में कार्यक्रमों में अपनी उपस्थित दर्ज करायी जबकि जयपुर जोन के अधिकांश अधिकारी प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाने के लिए शामिल हुए।

164 प्रकार के मसाले और खाद्य उत्पाद

दस दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला में राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रसिद्ध मसालों सहित 164 प्रकार के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गये।

कॉनफैड के प्रबंध निदेशक वी.के. वर्मा ने बताया कि देश में केवल राजस्थान ही एक मात्र एक राज्य है, जहां प्रति वर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों के विशिष्ट मसालों के साथ-साथ पंजाब, केरल, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के विश्वप्रसिद्ध एवं गुणवत्तायुक्त स्वादिष्ट मसाले व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में एयरकूल्ड डॉम बनाए गए हैं, जहां पर 10 प्रकार के साबुत गरम मसाले, 13 परम्परागत मसाले, 27 प्रकार के इंस्टेंट मसाले, 5 प्रकार के परम्परागत साबुत मसाले, 16 प्रकार के अचार, 26 प्रकार के शर्बत, 5 प्रकार की ठण्डाई, 5 प्रकार के मुरब्बे, 7 प्रकार की सूखी सब्जियां, ड्राईफ्रूट, डेयरी उत्पाद, खाद्यान्न एवं अनाज, तेल एवं अन्य खाने की सामग्री सहित 164 प्रकार के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

हर रोज लक्की ड्रा, अंतिम दिन मेगा ड्रा

मेले में प्रत्येक दो हजार रुपए की खरीद पर खरीदार को एक कूपन दिया गया, जिसमें हर रोज 5100, 3100 और 2100 रुपए का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लक्की ड्रा निकाला गया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम की स्टेज पर ड्रा निकाला जाता और विजेता को हाथों-हाथ उनके मोबाइल नम्बर पर सूचना दी जाती। इसके अलावा 5 हजार रुपए की खरीद पर, अन्तिम दिन मेगा लक्की ड्रा निकाला गया, जिसमें विजेता को प्रथम पुरस्कार 1.5 टन का स्पिलिट एयरकंडीशनर, द्वितीय पुरस्कार 220 लीटर का रेफ्रिजरेटर व तृतीय पुरस्कार माइक्रोवेव ऑवन दिया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बढ़ायी सहकार मसाला मेला की शोभा

जयपुर। जवाहर कला केंद्र में आयोजित किये गये राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला के दौरान प्रतिदिन सायंकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत 1 मई को अजमेर सम्भाग से हुई। कलाकारों ने चरी नृत्य, भवई नृत्य, घूमर नृत्य और कालबेलिया नृत्य के माध्यम से सहकार मसाला मेले में रौनक भर दी। अगले दिन 2 मई को कोटा जोन की ओर आयोजित कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लोक कलाकार हरिहर बाबा (प्रो. धन्नालाल मीणा) और उनके दल (रसरंग लोक कला मंडल, बोरखेड़ा) ने विभिन्न प्रकार के भवई नृत्य प्रस्तुत किये। उनके द्वारा माता के भजन पर बैलगाड़ी के पहिये के साथ पेडा भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, जल संरक्षण और सामाजिक पर्यावरण का संदेश देता मटकी भवई नृत्य, गिलास के ऊपर मटकी रखकर किया जाने वाला जल भवई नृत्य और राधा-कृष्ण की ब्रज होली के लिए प्रसिद्ध मयूर नृत्य को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया गया।

तीसरे दिन, 3 मई को भरतपुर सम्भाग की ओर से सनातन संस्कृति में रची बसी ब्रज की फूलों की होली से ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने बहुत ही खूबसूरती से, बृजभूमि के गीतों पर अद्भुत फूलों की होली खेलते हुए राधा-कृष्ण एवं गोपियों के माध्यम से द्वापर युग को साकार कर दिया। जयपुर जोन द्वारा 4 मई को आयोजित कार्यक्रम में तेजाजी का गायन हुआ और जादूगर ने हाथ की सफाई से दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

5 मई को बीकानेर जोन की ओर से पंजाबी की लोक संस्कृति व पारम्परिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों में जोश भर दिया। केसर भंगड़ा ग्रुप की इस धमाकेदार प्रस्तुति के दौरान कई बार ऐसा अवसर आया जब उपस्थिति अधिकारियों, कर्मचारियों एवं दर्शकों के साथ पूरा स्टेज ही झूमने लगा। अग्रिम पंक्ति पर विराजमान सहकारी अधिकारियों ने पंजाबी गीतों पर मस्ती के साथ डांस किया। पंजाबी परिवारों में विवाह पूर्व निकाली जाने वाली जागो की प्रस्तुति में पंजाब की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली।

जोधपुर जोन की ओर से 6 मई को आयोजित कार्यक्रम में जैसलमेर के प्रसिद्ध लंगा कलाकारों - छुगे खान एंड पार्टी (मंगणियार लोक संगीत संस्थान, हमीरा) ने राजस्थानी लोक गीतों से समा बांध दिया। इन लोक कलाकारों द्वारा कार्यक्रम की शुरूआती दौर में प्रस्तुत झिरमिर बरसे नेह गीत के साथ इन्द्रदेव ने जुगलबंदी की और 45 डिग्री से अधिक तापमान से झुलसती गुलाबी नगरी को शीतल फुहारों से राहत प्रदान की। इससे पूर्व छुगे खां ने शहनाई पर केसरिया बालम पधारो म्हारे देश के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की। उनके द्वारा प्रस्तुत अलगोजा वादन और कव्वाली छाप तिलक का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। सवाई खां और साथी कलाकारों ने झिरमिर बरसे नेह, गोरबंद नखरालो और बाबा बुल्ले शाह का सुफियाना गीत प्रस्तुत किया। शारदा सपेरा और सुनीता सपेरा ने राजस्थान का सुप्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया। आसीन खां ने कद आवो नी बालाजी, दमादम मस्त कलंकर कव्वाली पेश की। जाकिर खां और तारीफ खां ने ढोलक और खड़ताल की जुगलबंदी पेश की, जिसे दर्शकों की तालियों का पूरा साथ मिला।

विभागीय अधिकारियों की प्रतिभा देख अचम्भित हुए लोग

इससे पूर्व शुक्रवार शाम की सांस्कृतिक संध्या के दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने अपनी गीत-संगीत की प्रतिभा से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। एलएसडीबी कार्मिक दीपक एन्ड्रूज के बैंड पर सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार विजय कुमार शर्मा और उनकी अर्द्धांगिनी श्रीमती कोकिला शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार मुरार सिंह जाड़ावत, उप रजिस्ट्रार सीएल बुनकर, सहायक रजिस्ट्रार राकेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक राजीव थानवी, सहायक रजिस्ट्रार मोहम्मद रफीक, निरीक्षक श्यामसुंदर शर्मा, अपेक्स बैंक कार्मिक गणेश मीना, ज्वाइंट रजिस्ट्रार सोनल माथुर आदि ने बेहद खूबसूरत अंदाज में मधुर स्वरलहरियां बिखेरी। दर्शक दीर्घा में उपस्थित डॉ. संदीप शर्मा, मारूति पांडे, अनिता गोयल ने भी गीत प्रस्तुत किये जबकि सहायक रजिस्ट्रार सुमन धनेटवाल ने मदर्स-डे की पूर्व संध्या पर मां को समर्पित एक कविता प्रस्तुत की। मेला के दौरान सांस्कृति कार्यक्रमों का संचालन कॉनफैड में सहायक प्रबंधक वित्त लोकेश बाफना ने किया।

उदयपुर के कलाकारों की बेमिसाल प्रस्तुति

सांस्कृतिक संध्या की कड़ी में रविवार को अंतिम प्रस्तुति के रूप में उदयपुर की धरोहर संस्था के कलाकारों ने लोकनृत्यों के माध्यम से राजस्थान की विशाल सांस्कृतिक विरासत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मंच पर प्रस्तुत कर, मेल की शोभा में चार चांद लगा दिये। यह पूरे आयोजन की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में से एक रही।

उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम ने मसाला मेला के स्टेंटर्ड को नयी ऊंचाई प्रदान की। प्रत्येक प्रस्तुति से पहले एंकर हिमानी जोशी ने अपनी मधुर आवाज में नृत्य से सम्बंधित राजस्थानी संस्कृति की व्याख्या की और उस नृत्य की प्रस्तुति में समय के साथ आए परिवर्तन से उपस्थित दर्शकों को परिचित कराया।

प्रत्येक नृत्य प्रस्तुति की पृष्ठभूमि में लंगा कलाकारों ने अपनी सधी हुई गायकी से, राजस्थानी गीतों की सुरीली प्रस्तुति दी। लोक कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नृत्य कलाकारों ने संगीत की शैली व मरूधरा की वैभवशाली परम्परा के अनुरूप एक से एक बढ़कर गरिमामयी एवं आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किये।

परम्परागत गीत-नृत्यों ने मन मोहा

अतिथियों के स्वागत में प्रस्तुत किया जाने वाला केसरिया बालम पधारो म्हारै देश हो या ऊंट के श्रृंगार पर आधारित प्रसिद्ध गीत गोरबंद नखरालो, राजशाही के समय में उच्च कुलीन घरानों की महिलाओं द्वारा खुशी के अवसर पर प्रस्तुत किया जाने वाले घूमर नृत्य हो या पश्चिम राजस्थान के इलाकों में कुएं से पानी लेकर नाचती-गाती आती हुई महिलाओं का भवाई नृत्य अथवा उत्तर राजस्थान के गुर्जर बहुल्य क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा सिर पर धातु का बर्तन रख, उसमें आग जलाकर किया जाने वाला चक्री नृत्य, इन सब को धरोहर संस्था के मझे हुए कलाकारों ने इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि दर्शक अचिम्भित रह गये।

पौराणिक नृत्यों ने किया आनंदित

भगवान विष्णु पर आधारित विष्णु चक्र नृत्य और राधा-कृष्ण पर आधारित मयूर नृत्य ने दर्शकों को आनंदित कर दिया। इन पौराणिक प्रस्तुतियों से हर्षित महिला सहकारी अधिकारियों ने मयूर नृत्य करते कलाकारों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। लंगा कलाकारों की ढोलक-खड़ताल की जुगलबंदी और अंत में प्रस्तुत किये गये सूफी गीत दमादम मस्त कलंदर से समां बांध दिया।

प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने किया मसाला मेले का अवलोकन

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने 4 मई को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2022 का अवलोकन किया। मेले में विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण करने के दौरान श्रीमती गुहा ने कहा कि सहकारिता का मूल उद्देश्य आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय सेवा के माध्यम से सहकारिता की भावना को साकार करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में और नवाचारों के माध्यम से राज्य में सहकारिता एक विशिष्ट पहचान कायम करेगा।

श्रीमती श्रेया गुहा ने इस मौके पर मसाला विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं से मिलकर मेले का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सहकारिता विभाग का एक अनूठा प्रयास है, जिसके माध्यम से हम शुद्ध मसालों एवं खाद्य पदार्थों को आमजन की रसोई तक पहुंचा कर वर्तमान एवं आगे की पीढ़ी के स्वास्थ्य को समृद्ध बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से हम एक ही छत के नीचे प्रदेश के सभी क्षेत्रों के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों के विशिष्ट मसालों एवं उत्पादों को पूर्ण शुद्धता के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं।

कॉनफैड के प्रबंध निदेशक वी.के. वर्मा ने प्रमुख शासन सचिव को बताया कि मेले में जयपुरवासियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार मसालों एवं अन्य उत्पादों की खरीद की जा रही है। कॉनफैड द्वारा पहली बार जैविक मसालों की बिक्री की जा रही है, जिसे लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में पसंद किया गया है।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का पुरस्कार वितरण समारोह

सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां

मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के घोटाले के बहाने से सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर साधा निशाना

जयपुर (सहकार गौरव)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के बहाने से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने का प्रयास किया है। गहलोत पहले भी कई बार संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शेखावत का नाम लेते रहे हैं। इस मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर निवेशकों के 950 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि हड़प जाने का आरोप है। सहकारिता विभाग को संजीवनी सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों का धन हड़पने की 31 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के घोटालों और प्राप्त शिकायतों की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में मल्टी स्टेट सोसायटियों के साथ बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के सम्बंध में भी लिखा जाए। सीएम ने कहा कि विभागीय अधिकारी राज्य में कार्यरत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें।

मल्टी स्टेट सोसायटियों के विरुद्ध 90 हजार शिकायतें

श्री गहलोत ने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों ने अनुचित तरीके से राजस्थान के लाखों लोगों की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को नुकसान पहुंचाया है। ऐसी सोसायटियों के सम्बंध में राज्य सरकार को 94164 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के घोटाले को लेकर लगभग 31 हजार से अधिक तथा आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ 41 हजार से अधिक शिकायत है, जिनमें लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्राधिकार वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव के घोटालों और अनियमितताओं से भविष्य में आमजन के बचाव के लिए सोसायटियों पर तुरंत रोक लगाएं।

विजिलेंस कमेटी द्वारा किए गए निरीक्षण

श्री गहलोत की जानकारी में लाया गया कि मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा घोटालों व अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान की अध्यक्षता में गठित विजिलेंस कमेटी के निर्देशन में उक्त सोसायटियों का निरीक्षण करवाया जा रहा है। प्रदेश में ऐसी 50 सोसायटी हैं, जिनमें से 12 समितियां अवसायनाधीन हैं। शेष 38 का विजिलेंस ऑथोरिटी के निर्देशन में निरीक्षण हो रहा है। अभी तक 27 सोसायटी की रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रकार की सोसायटी के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता लाई जाए।

पैक्स की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए करें प्रयास

श्री गहलोत ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए। खाद-बीज वितरण, भंडारण जैसे कार्यों के अतिरिक्त प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर यूनिट लगाई जाए। फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) नीति के तहत पैक्स, लैम्पस को और मजबूती प्रदान की जाए।

18101 करोड़ रूपए के फसली ऋण वितरित

बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि अल्पकालीन फसली ऋण वितरण (2021-22) में 18500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। इसमें से 31 मार्च 2022 तक 18101 करोड़ रुपए (98 प्रतिशत) वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020 से अब तक 220 से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री सम्बल योजना की राशि दुग्ध समितियों के बैंक खाते में हस्तांतरित

अजमेर। अजमेर सरस डेयरी हाईटेक होकर डिजिटलाइजेशन का पूरा उपयोग करते हुए पशुपालकों को अपने दूध बेचान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरण करने का निर्णय किया हैं। इसे गुरुवार को साकार रूप दिया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सम्बल योजना में 5 रुपए प्रति लीटर की राशि का भुगतान करते हुए अप्रेल माह का सम्पूर्ण बकाया पशुपालकों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। 350 समितियों की 4 करोड़, 80 लाख रुपए की राशि डेयरी प्रबंधन द्वारा बैंक में जमा करवा दी गई है। लगभग डेढ़ सौ समितियों से जुड़े सदस्य व दुग्ध उत्पादको के खाते में यह राशि स्थानांतरित की गई। शेष 200 समितियों के द्वारा बैंक की व डेयरी की कागजी कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण उनका भुगतान रोका गया हैं उसे जल्द ही इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 350 समितियों से लगभग 36 हजार पशुपालक जुड़े हुए हैं ,जिनके खातों में अप्रेल माह की संपूर्ण राशि स्थानांतरित कर दी गई है।

एक साल में 20 लाख रुपए से अधिक राशि के बैंकिंग लेनदेन पर नए नियम लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपए से अधिक राशि जमा करने या निकालने के लिए पैन या आधार देना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022, के तहत नए नियम बनाए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नए नियमों के लागू होने के बाद अब अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि जमा करता है या रुपए निकलवाता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा। यहीं नहीं, अब किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में बिना पैन और आधार के करंट या कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा।

क्या है सरकार की मंशा

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की मंशा ऐसे लोगों को लाने की है, जो अधिक पैसे का लेन-देन करते हैं लेकिन उनके पास पैन नम्बर नहीं है। इसलिए वे बिना टैक्स चुकाए आसानी से भाग जाते हैं और उनके पास काला धन है। नए नियमों के लागू होने से सरकार के लिए धन के प्रवाह पर नजर रखना आसान हो जाएगा, जिससे आयकर विभाग को काफी मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी व्यक्ति का बैंक खाता पैन से लिंक हो जाने के बाद, कर अधिकारियों के लिए लेनदेन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। सरकार उन लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए अपने करदाता आधार का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जो बड़े लेनदेन कर रहे हैं लेकिन जिनके पास पैन नहीं है।

सहकारी सोसाइटियों को 31 मई तक ऑडिटर की नियुक्ति करनी होगी

बीकानेर (सहकार गौरव)। सहकारी समितियों के संचालक मण्डल द्वारा वर्ष 2021-22 के आंकड़ों की ऑडिट के लिए स्वयं प्रस्ताव लेकर विभागीय पैनल के सी.ए. या सी.ए. फर्म को नियुक्त करने या विभागीय ऑडिटर के पैनल को चुनने की अंतिम तारीख आगामी 31 मई 2022 निर्धारित की गई है।

सहकारी समितियों के क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी राजेश टाक ने बताया कि वैधानिक अंकेक्षण के लिए सीए या सीए फर्म की यह नियुक्ति करते हुए इसके प्रस्ताव 31 मई तक पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति ऑडिट से सम्बंधित रजिस्ट्रार संयुक्त मुख्य अंकेक्षक (जनरल या दुग्ध) जयपुर, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी या सम्बंधित विशेष लेखा परीक्षक को देनी होगी।

ऑडिट नहीं करवाने पर संचालक मंडल होगा दोषी

टाक ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 व नियम 73 के अनुसार ऑडिटर की नियुक्तिकर 30 सितम्बर तक ऑडिट व आमसभा करवानी तथा आमसभा में ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर पूर्ति रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी आवश्यक है। इसमें असफल रहने पर सोसायटी के संचालक मण्डल के दोषी सदस्यों को अधिनियम की धारा के प्रावधानों के तहत निर्योग्य ठहराया जा सकता है। यह सदस्य आगामी 6 साल तक इस सोसाइटी चुनाव लडने से भी निर्योग्य हो जाएगा।

बीकानेर सम्भाग में 2296 सोसाइटी में होनी है ऑडिट

उन्होंने बताया कि बीकानेर खण्ड के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में कुल 2296 सहकारी समितियों की ऑडिट इस वर्ष करवाई जानी है। इनमें 54 केन्द्रीय समिति हैं। ऑडिट से गत वर्ष शेष रही समितियों की ऑडिट भी इसके साथ ही की जानी है।

एक और सहकारी बैंक पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई का कहना है कि बिना उसके अनुमति के बैंक, किसी को लोन, अनुदान नहीं दे सकता और नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता है। इसके अलावा किसी तरह का निवेश भी नहीं कर सकता है। वहीं अन्य प्रतिबंधों के बीच अपनी किसी भी सम्पत्ति या सहम्पत्ति का निपटारा नहीं कर सकता है। आरबीआई के निर्देश के उपरांत खाताधारक इस बैंक में अपनी जमा राशि नहीं निकाल पाएंगे तथा कुछ बैंकिंग सुविधा का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। आरबीआई ने शुक्रवार को कर्जदाता बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है।

सहकारी बैंककर्मियों के लिये 16वें वेतन समझौते के मांगपत्र पर वार्ता शुरू करने की मांग

आमेरा के नेतृत्व में प्रमुख शासन सचिव से मिला यूनियन का प्रतिनिधिमण्डल

जयपुर (सहकार गौरव)। ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन व ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रान्तीय महासचिव सूरजभान सिंह आमेरा के नेतृत्व में सहकारी बैंककर्मियों के प्रतिनिधिमण्डल ने सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा से मुलाकात कर राज्य के सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए जनवरी, 2019 से देय 16वें वेतन समझौते के माँगपत्र पर वार्ता शुरू करने की माँग की।

आमेरा ने बताया कि राज्य के अपेक्स बैंक, 29 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक एवं 36 पीएलडीबी के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए जनवरी 2019 से वेतनमान, भत्तों, सुविधाओं व सेवा शर्तों में सुधार तथा पेंशन योजना लागू करने के माँगपत्र पर सरकार द्वारा गठित कमेटी की संगठन के साथ द्वि-पक्षीय वार्ता कर वेतन समझौता लागू किया जाना लम्बित है।

आमेरा ने सहकारी बैंकों में सुशासन व आर्थिक सुदृढ़ता के लिए प्रबन्ध निदेशक पद पर 'फिट एण्ड प्रोपर' मापदण्ड के तहत योग्य अधिकारियों का चयन करने, सहकारी बैंकों में स्टाफ स्ट्रेन्थ पुनर्निधारण कर भर्ती करने, पैक्स कार्मिकों के लिए कैडर व्यवस्था लागू करने तथा भूमि विकास बैंकों के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने आदि मुद्दों पर भी विस्तार से वार्ता कर समाधान की जरूरत बतायी। प्रतिनिधिमण्डल में अपेक्स बैंक से सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिषेक रायजादा, जयपुर सीसीबी से विजय पारीक, अनिता चन्देल, राज्य भूमि विकास बैंक से भंवरलाल, विनीता मण्डल, राजेश गोठवाल एवं मुकेश कुमार उपस्थित रहे।

50 हजार महिला स्वयं सहायता समूह गठित किये जाएंगे : गहलोत

महिला सहकारी बैंक की पहली शाखा जयपुर में आरम्भ होगी

जयपुर (सहकार गौरव)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्ययोजना बना ली गई है, जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। इन स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी व बैंक ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।

शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि महिला को-ऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा जल्द ही जयपुर में खोली जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में मेट व्यवस्था के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक महिला मेटों के नियोजन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में 100 प्रतिशत महिला मेट का नियोजन किया जा चुका है, जो एक ऐतिहासिक पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में स्थित ग्रामीण तथा शहरी हाट बाजारों का संचालन अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा ताकि इनका वर्षभर उपयोग हो सके। मनरेगा में श्रमिकों द्वारा स्वयं कार्य की मांग करने के लिए मोबाइल एप बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिससे श्रमिकों के रोजगार का अधिकार सुनिश्चित होगा। जॉब कार्ड में जनआधार की एंट्री के लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इससे जॉब कार्ड की डुप्लीकेशन की समस्या समाप्त होगी।

मनरेगा में बजट कटौती चिंताजनक

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में कटौती पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए भारत सरकार द्वारा सामग्री मद में 3000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जिसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि विभाग प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजुवास के डॉ. देवीसिंह और डॉ. टीकम चन्द गोयल हुए सम्मानित

बीकानेर। सोसायटी फॉर वेटरनरी एण्ड एनीमल हसबेड्री एक्सटेशंन (एस.वी.ए.एच.ई.) का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 'पशुपालन विकास हेतु प्रसार कार्यक्रमों के बहुवादी दृष्टिकोण' विषय पर पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। सम्मेलन में वेटरनरी कॉलेज, बीकानेर के सहायक आचार्य डॉ. देवीसिंह को 'इनोवेटिव एक्सटेशन एजुकेशनिस्ट' अवार्ड और डॉ. टीकमचन्द गोयल, सहायक आचार्य, वेटरनरी कॉलेज, नवानियां, उदयपुर को 'यंग एक्सटेशन साईंटिस्ट' अवार्ड प्रदान किया गया। पीजीआईवीईआर, जयपुर के सहायक आचार्य डॉ. अशोक बेन्दा के शोध पत्र वाचन को प्रथम एवं डॉ. सुभाष यादव के शोध पत्र वाचन को द्वितीय बेस्ट शोध पत्र वाचन पुरस्कार मिला। इस उपलब्धि के लिए फैकल्टी सदस्यों ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी। तीन दिवसिय सम्मेलन में वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर सहित 16 राज्य के लगभग 200 वैज्ञानिक ने सम्मिलित हुए।

श्रीगंगानगर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली का बहिष्कार समाप्त

श्रीगंगानगर। सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन श्रीगंगानगर ने ऋण वितरण एवं वसूली कार्य का बहिष्कार समाप्त कर दिया है। जिलाध्यक्ष जसविन्द्र सिंह बराड़ और संयोजक ओमप्रकाश रोझ ने बताया कि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग से यूनियन प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के उपरांत, बहिष्कार को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इन्होंने बताया कि एमडी श्री गर्ग के साथ लगभग दो दर्जन व्यवस्थापकों की मौजूदगी में हुई वार्ता में अधिककांश मुद्दों पर सहमति बन गयी है। ऐरियर ब्याज के मुद्दे पर एमडी ने यूनियन द्वारा सुझावित -सादुलशहर और रिडमलसर ब्रांच में बैंक अधिकारियों की एक कमेटी द्वारा एरियर ब्याज की जांच करवाने और जांच रिपोर्ट में शिकायत सही पाए जाने पर, समस्त ब्रांचों में एरियर ब्याज की गणना करवाकर, राशि समायोजित करने का आश्वासन दिया। इसके दो दिन पश्चात लिखित आदेश भी जारी कर दिये गये। हिस्सा राशि के मुद्दे पर एमडी ने कहा कि नये फसली ऋण वितरण में 20 प्रतिशत राशि बढाकर दी जाएगी, जिससे समितियों की अधिक हिस्सा राशि का बड़ा हिस्सा समायोजित हो जाएगा। हिस्सा राशि पर ब्याज के सवाल पर एमडी ने कहा कि बैंक की आगामी आमसभा में ब्याज की अपेक्षा, डिविडेंट दिये जाने पर चर्चा की जा सकेगी। इसके अलावा, एमडी संजय गर्ग ने यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को स्क्रीनिंग की मांग पर राज्य सरकार के स्तर पर आदेश होते ही, पात्र कार्मिकों की स्क्रीनिंग करने का भी आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष श्री बराड़ ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जिला स्तरीय मांगों का निस्तारण करते हुए, तुरंत आदेश जारी कर दिये गये, जिसके उपरांत ऋण वितरण एवं वसूली कार्य का बहिष्कार समाप्त कर दिया गया।

प्रथम पृष्ठ का शेष

जून-जुलाई में ...

कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ऐसे प्रकरणों में संशोधन को पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाए और तत्पश्चात आगामी 10 दिवस में सोसाइटी स्तर पर वार्डों का गठन और वार्डों के आरक्षण का कार्य पूर्ण किया जाए। इसी प्रकार, जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आमसभा में संशोधन को अस्वीकार किया गया है, ऐसे प्रकरणों में, उपलब्ध विकल्पों के अनुरूप यथोचित अग्रिम कार्यवाही की जाए।

वीसी के दौरान पैक्स, लैम्पस के प्रस्तावित चुनावों के लिए कार्मिकों की उपलब्धता, निर्वाचन योग्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूचना, संवेदनशील सोसाइटियों की सूची, प्रस्तावित रूट चार्ट, चुनाव के प्रस्तावित चरणों और कार्मिकों के प्रशिक्षण पर चर्चा की गयी।

सहकार मसाला मेला ...

एडिशनल रजिस्ट्रार और मेला कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा, सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार दुर्गालाल बलाई और कॉनफैड के प्रबंध निदेशक वी.के. वर्मा ने सहकार मसाला मेले में सर्वाधिक बिक्री के लिए अन्य प्रदेशों की श्रेणी में केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन, शीर्ष संस्थाओं में कॉनफैड, जिला भण्डारों में कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार व क्रय विक्रय सहकारी समितियों की श्रेणी में भीनमाल केवीएसएस को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। मेले में कारोबार एवं डिसप्ले की दृष्टि से समितियों को पुरस्कृत किया गया है। बिक्री के आधार पर शीर्ष संस्थाओं में प्रथम कॉनफैड, द्वितीय स्थान तिलम संघ व तृतीय स्थान पर जयपुर डेयरी रहा। मार्केटिंग सोसाइटी में भीनमाल केवीएसएस प्रथम, मथानिया केवीएसएस द्वितीय एवं आबूरोड केवीएसएस तृतीय स्थान पर रही। सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की श्रेणी में कोटा, उदयपुर व जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मेले में उपस्थिति दर्ज कराने वाली एक मात्र पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति को भी पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ डिसप्ले के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में कृभको, इफको तथा शीर्ष सहकारी संस्थाओं में राजफैड, कॉनफैड, तिलम संघ, जयपुर डेयरी एवं अपैक्स बैंक को सम्मानित किया गया। राज्य विशेष के विशिष्ट उत्पादों एवं मसालों की बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु मार्केटफैड केरल, इरोड तमिलनाडु, टैनफैड तमिलनाडु और पंजाब की सहकारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। जिला उपभोक्ता भण्डारों की श्रेणी में उदयपुर, श्रीगंगानगर व कोटा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। केवीएसएस की श्रेणी में नागौर, आबूरोड एवं जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

प्रदेश में 10 पैक्स और 9 लैम्पस के गठन की स्वीकृति जारी

जयपुर। सहकारिता विभाग द्वारा मई माह के प्रथम पखवाड़ा में राज्य में 19 नई ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स और लैम्पस) के गठन की स्वीकृति जारी की गयी है। रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि 1 मई से 15 मई के दौरान सम्बंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रतापगढ़ में 6 लैम्पस, बारां में 3 लैम्पस, दौसा में 3 पैक्स, बाड़मेर में 2 पैक्स और सीकर में 5 ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति जारी की गयी है।

जिला प्रतापगढ़ (6 लैम्पस)

नाम पैक्स/लैम्पस	पंचायत समिति
नागदी	अरनोद
बजरंगगढ़	प्रतापगढ़
सेमलोपुर	प्रतापगढ़
काजलीखेड़ा	प्रतापगढ़
केसरपुरा	प्रतापगढ़
मचलाना	प्रतापगढ़

जिला बारां (3 लैम्पस)

ख्यावदा	किशनगंज
परानियां	किशनगंज
बाल्दा	शाहबाद

जिला दौसा (3 पैक्स)

चावण्डेडा	दौसा
इन्दावा	लालसोट
करनावर	बांदीकुई

जिला बाड़मेर (2 पैक्स)

खूमे की बेरी	धौरिमना
मगरा	गडरारोड

जिला सीकर (5 पैक्स)

गोडावास	नीमकाथाना
पनिवाहरवास	खण्डेला
ढाल्यावास	खण्डेला
बीदसर	लक्ष्मणगढ़
रघुनाथगढ़	पिपराली

प्रदेश में 1000 से अधिक पशु शिविर और 198 चारा डीपो स्वीकृत-मेघवाल

जयपुर (सहकार गौरव)। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि गर्मी के मौसम के दृष्टिगत प्रदेश भर में पशु संरक्षण एवं पेयजल परिवहन की गतिविधि प्रभावी तरीके से संचालित की जा रही हैं। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना और पशुओं के लिए चारा उपलब्धता सुनिश्चित करना, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

श्री मेघवाल ने रविवार को बताया कि आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर एवं चारा डीपो संचालित करने के दिशा-निर्देश 10 जनवरी को जारी कर दिए गए। इसकी अनुपालना में अब तक जैसलमेर में 738, बाड़मेर में 286, जोधपुर में 3 और पाली में 2, कुल 1029 पशु शिविर स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार बाड़मेर में 49, बीकानेर में 44, जोधपुर में 39 तथा पाली में 66 सहित कुल 198 चारा डीपो स्वीकृत किए जा चुके हैं। चारा की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग द्वारा 4 मई को सभी जिला कलक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि गौशाला को छोड़कर कोई भी व्यापारी 100 मेट्रिक टन से अधिक चारा भंडारण नहीं करेगा।

केंद्र सरकार ने अनुरोध, चारे को ईसी एक्ट के दायरे में लाया जाए

मंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों एवं जिलों से चारे की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग को निर्देशित किया गया है। चारे की उपलब्धता एवं दरों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब में दल भिजवाए गए हैं। मध्यप्रदेश एवं हरियाणा से आने वाले चारे को राजस्थान में निर्बाध रूप से आने देने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चारे को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को निवेदन किया गया है।

किसानों को सस्ते ऋण व प्राथमिक बैंकों की आर्थिक मजबूती के लिए पीएलडीबी का एसएलडीबी में मर्जर करने का सुझाव

जयपुर (सहकार गौरव)। ऑल राजस्थान सहकारी बैंक एम्पलॉइज यूनियन ने किसानों को देश में सबसे कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने और राज्य की सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (पीएलडीबी) की वित्तीय स्थिति सुदृढ करने के लिए प्राथमिक बैंकों का राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (एसएसडीबी) में मर्जर करने का सुझाव दिया है।

इस सम्बंध में यूनियन के महासचिव मोहन कटारा की ओर से नाबार्ड को प्रेषित पत्र में बताया गया कि राज्य में कार्यरत 36 पीएलडीबी द्वारा वर्तमान में 10.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर किसानों को कृषि एवं अकृषि कार्यों हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समय पर ऋण का चुकारा करने वाले ऋणी को राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार, अच्छे ऋणियों को सरकार केवल 5.15 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा रही है।

कटारा के अनुसार, दीर्घकालीन ऋण वितरण के लिए नाबार्ड द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को 6.65 वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। राज्य बैंक, प्राथमिक बैंक को 7.65 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध करवा रहे हैं। यही ऋण किसान को 10.15 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है।

कटारा ने सुझाव दिया है कि यदि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर एकात्मक प्रणाली (यूनिटरी सिस्टम) कर दिया जाये तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा बना दी जाये तो कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना के पश्चात किसानों को मात्र 2.65 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे न केवल राजस्थान के किसानों को देश में सबसे कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, बल्कि पीएलडीबी का कारोबार बढेगा और पीएलडीबी की वित्तीय स्थिति सुदृढ होगी। पत्र की प्रतिलिपि सहकारिता मंत्री, प्रमुख शासन सचिव और सहकारिता रजिस्टार को भी प्रेषित की गयी हैं।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक मनीष मुंजाल के आदेशानुसार न्यू भाटिया प्रिंटर्स, 125 गोल बाजार, श्रीगंगानगर से मुद्रित तथा 392 चांदनी चौक, रामनगर, श्रीगंगानगर से प्रकाशित। मो.: 9782056056 - सभी प्रकार के वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र श्रीगंगानगर होगा। RAJHIN/2013/57037